भारतीय विश्वविद्याल संघ द्वारा पूर्वी क्षेत्र के कुलपतियों की बैठक में माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया का अभिभाषण

दिनांक 22 नवंबर 2023, बुधवार	समय : 9.30 AM	स्थान : रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी

- भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) के अध्यक्ष प्रो. जी. डी. शर्मा जी.
- महासचिव डॉ. पंकज मित्तल जी,
- संयुक्त सचिव डॉ. अलोक कुमार मिश्रा जी,
- रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉ. अशोक कुमार पंसारी जी,
- कुलपति डॉ. एस.पी. सिंह जी,
- उपस्थित अन्य अतिथिगण,
- बैठक में भाग ले रहे कुलपतिगण
- देवियों और सज्जनों

नमस्कार !

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के नेतृत्व में आज यहां आयोजित पूर्वी क्षेत्र के कुलपितयों के इस दो दिवसीय सम्मेलन में एक ही छत के नीचे आप सभी से मिलना मेरे लिए वास्तव में एक शानदार अवसर है।

आप सभी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि आप सभी देश में उच्च शिक्षा के अगुआ हैं। युवाओं के समग्र विकास के लिए शिक्षा नीति के उचित क्रियान्वयन हेतु आपका मार्गदर्शन अत्यन्त आवश्यक है ताकि ये युवा बहु-विषयक शिक्षा के माध्यम से देश की प्रगति में योगदान देने में सक्षम हो सकें।

देवियों और सज्जनों,

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) 1925 में स्थापित देश के प्रमुख शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह उच्च शिक्षा, खेल और संस्कृति में भारत सरकार के लिए एक शोध-आधारित नीति सलाहकार संस्थान है। अपनी स्थापना के बाद से, यह देश में उच्च शिक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में, यह भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और समन्वय की सुविधा प्रदान करती है और विश्वविद्यालयों और सरकार और सामान्य हित के मामलों में अन्य देशों में उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के बीच संपर्क करती है।

मुझे बताया गया है कि एआईयू की प्रमुख गतिविधियों में से एक उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर कुलपतियों की बैठक आयोजित करना है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में पांच क्षेत्रीय बैठकें और एक राष्ट्रीय कुलपति बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठकें न केवल सामूहिक ज्ञान के माध्यम से उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच हैं, बल्कि उच्च शिक्षा के प्रणेताओं की आवाज को उचित अधिकारियों तक ले जाने में उत्प्रेरक भूमिका निभाने के लिए भी महत्वपूर्ण मंच है।

इस संदर्भ में, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एआईयू ने 2023-24 में सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कुलपतियों के सम्मेलनों का आयोजन करने का निर्णय लिया है।

'आजादी का अमृत महोत्सव' यानी भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का समारोह भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण संकल्प के साथ समाप्त हुआ, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के उत्सव के 75 वर्ष से 100 वर्षों के बीच की अवधि को अमृत काल के रूप में सीमांकित किया गया है।

'अमृत काल' सरकार द्वारा 2047 तक 25 साल की अवधि को चिह्नित करने के लिए उत्प्रेरक शब्द है, जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। यह अगले 25 वर्षों के लिए सरकार का रोडमैप है।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2020 को 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक अग्रगामी, अभिनव, लोकतांत्रिक और शिक्षार्थी-केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की।

इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों में न केवल विचार में, बल्कि भावना, बुद्धि और कर्मों में भी भारतीय होने को बोध हो। इसका उद्देश्य ज्ञान, कौशल, मूल्यों और स्वभावों को विकसित करने के साथ-साथ मानवाधिकारों, सतत विकास और जीवन और वैश्विक कल्याण के प्रति जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करना है। इस दिशा में कई पहल की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एनसीईआरटी, आईआईटी जैसे संगठनों ने मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की हैं।

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों का मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए, देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में एआईयू ने 'उच्च शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली (बीकेएस) को एकीकृत करना' विषय पर पूर्वी क्षेत्र के कुलपतियों का सम्मेलन आज आयोजित किया है। हर्ष का विषय है कि इस सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी की प्रतिष्ठित असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है।

आशा है कि इस सम्मेलन में विषयगत चर्चा से वैदिक काल के हमारे मजबूत पारंपरिक/स्वदेशी ज्ञान के आधार पर भारतीय ज्ञान प्रणाली (बीकेएस) के शिक्षण के लिए कुछ केंद्रित मार्गदर्शक बिंदु विकसित होंगे।

शिक्षकों और विद्यार्थियों के मन में कुछ भ्रम भी होंगे, जिनका समाधान किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बीकेएस /आईकेएस के लिए दिशानिर्देश दिए हैं, जिन पर भी विधिवत विचार किया जा सकता है।

मैं प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों से अपील करता हूं कि वे अपने संस्थानों में एक बीकेएस केंद्र या प्रकोष्ठ स्थापित करें, जिससे निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों को उचित परिश्रम के साथ संचालन किया जा सके।

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि कुल अनिवार्य क्रेडिट का 5 प्रतिशत बीकेएस /आईकेएस के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।

मैं राष्ट्रीय शीक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन के कम से कम दो और पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला एनईपी के संदर्भ में परीक्षा सुधार और दूसरा एनईपी की रोशनी में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की समझ और उचित क्रियान्वयन। जहां तक मुझे जानकारी है, इन विषयों पर ठीक से काम नहीं हुआ है।

एनईपी 2020 के कई अन्य विषय हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य में इस तरह के सम्मेलनों में इन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए।

अंत में, मैं सम्मेलन में भाग ले रहे कुलपतियों एवं गणमान्य व्यक्तियों और इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ और रॉयल ग्लोबल विश्वविद्यालय के प्रबंधकों को धन्यवाद देता हूं और उच्च शिक्षा के विकास में आपके कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

जय हिन्द।